Regd. No. CHD/0093/2012-2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, THURSDAY, MARCH 1, 2012
(PHALGUNA 11, 1933 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 1st March, 2012

No. 13—HLA of 2012/13.—The Haryana Rural Development (Amendment) Bill, 2012, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :--

Bill No. 13—HLA of 2012

THE HARYANA RURAL DEVELOPMENT (AMENDMENT) BILL, 2012

A

BILL

further to amend the Haryana Rural Development Act, 1986.

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows : --

1. This Act may be called the Haryana Rural Development (Amendment) Act, 2012. Short title.

2. In sub-section (1) of section 5 of the Haryana Rural Development Act, 1986,— Amendment of section 5 of Haryana Act 6 of 1986.

(i) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and

(ii) the following provisos shall be added at the end, namely:- -

"Provided further that rate of fee on cotton with effect from 1st November, 2011 shall be 0.8 per centum:

Provided further that rate of fee on potato during the period from 22nd December, 2011 to 31st March, 2012 shall be 1 per centum.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to discourage the export of cotton outside the State and for better compliance in the collection of rural development fee and to give relief to the potato growers, the State Government proposes to reduce the rural development fee on cotton with effect from1.11.2011 from 2% to 0.8% and on potato with effect from 22-12-2011 till 31-03-2012 from 2% to 1% by amending section 5 of the Haryana Rural Development Act, 1986.

BHUPINDER SINGH HOODA,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 1st March, 2012.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2012 का विधेयक संख्या 13-एच० एल० ए०

हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) विधेयक, 2012

हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986
को आगे संशोधित
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) अधिनियम, 2012, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986, की धारा 5 की उप-धारा (1) में,— 1986 के हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 5 का संशोधन।

(i) अन्त में विद्यमान चिह्न "।" के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिए जाएंगे, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि प्रथम नवम्बर, 2011 से कपास पर फीस की दर 0.8 प्रतिशत होगी :

परन्तु यह और कि 22 दिसम्बर, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के दौरान आलू पर फीस की दर एक प्रतिशत होगी।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

कपास के राज्य से बाहर निर्यात में कमी और ग्रामीण विकास फीस की वसूली में अच्छी बढ़ोतरी तथा आलू उत्पादकों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार. कपास पर ग्रामीण विकास शुल्क को 1.11.2011 से 2 प्रतिशत से घटा कर 0.8 प्रतिशत तथा आलू पर 22.12.2011 से 31.03.2012 तक 2 प्रतिशत से घटा कर 1 प्रतिशत करने के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 की धारा 5 में संशोधन करने का प्रस्ताव करती है।

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा,
मुख्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ .
1 मार्च, 2012

सुमित कुमार,
सचिव।

49661—H.V S.—H.G.P., Chd.